नवभारत 04
सतना, रविवार, 05 जुलाई, 2026

छत्रसाल उद्यान में बंद पड़ी बच्चों की ट्रेन, खुले नाले से हो रहे हादसे

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। शहरवासियों को स्वस्थ और मनोरंजक वातावरण देने के उद्देश्य से विकसित किया गया छत्रसाल उद्यान आज खुद बदहाली का शिकार बन गया है। शहर के सबसे बड़े इस पार्क में बच्चों की पसंदीदा छुक-छुक ट्रेन लंबे समय से बंद पड़ी है, फव्वारे ठप हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नदारद है और पाथ-वे के किनारे खुला नाला हादसे को आमंत्रण दे रहा है।

नगर पालिका प्रशासन को इन समस्याओं की जानकारी होने के बावजूद सुधार की दिशा में कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है। शहर में मैथिलीशरण गुप्त पार्क, चंद्रशेखर पार्क, बलदेव पार्क, बेनीसागर स्थित सुदर्शन पार्क, टॉकीज के पास का पार्क और सतना नाका स्थित पार्क सहित आधा दर्जन से अधिक उद्यान हैं लेकिन सबसे अधिक उपेक्षा शहर के मध्य स्थित छत्रसाल उद्यान की हो रही है। बच्चो के मनोरंजन और आमजन की सुविधा के लिये बनाई गई कई व्यवस्थाएं अब केवल शो-पीस बनकर रह गई है। उद्यान में टहलने के लिये बनाए गये पाथ वे के किनारे की बाउन्ड्री कई स्थानो पर टूटी हुई है। इसके ठीक पास खुला नाला होने से बच्चों और बुजुर्गो के लिये दुर्घटना का खतरा बना रहता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में परिवार और बच्चे पार्क पहुंचते है, लेकिन सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम नही किये गए है। स्थानीय लोगो का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नही सुधारी गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

नियमित साफ सफाई नही, आवारा कुत्तो का डेरा, सुविधाघर में ताला - नगर पालिका की लापरवाही के कारण उद्यान में नियमित साफसफाई भी नही हो रही है। जगह जगह कचरा बिखरा रहता है जिससे सुबह शाम टहलने आने वाले लोगो को परेशानी उठानी पड़ती है। पार्क के अंदर आवारा कुत्तो का जमावड़ा रहता है। उद्यान में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पानी की टंकी, नल और सुविधाघर का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्तमान में सुविधाघर पर ताला लटका हुआ है और नलों से पानी नहीं आ रहा।

भीषण गर्मी में पार्क आने वालों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है।

अन्य पार्कों की भी नहीं हो रही देखभाल

छत्रसाल उद्यान ही नहीं, शहर के अन्य पार्क भी उपेक्षा का शिकार हैं। कई पार्कों में पेड़-पौधों की समय पर छंटाई नहीं होती, घास बढ़ी रहती है और सुंदरता खत्म होती जा रही है। कुछ पार्क शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाते हैं। जालियां टूट चुकी हैं और नगर पालिका के कर्मचारी महीनों तक निरीक्षण करने नहीं पहुंचते, जिससे शहर के पार्क अपनी उपयोगिता और आकर्षण दोनों खोते जा रहे हैं।

दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज पर आयुक्त ने की सराहना

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत भारत की हस्तलिखित विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इस मिशन का नोडल विभाग है। संस्कृति विभाग द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में ज्ञान भारतम हेतु हस्तलिखित पांडुलिपियों का सर्वे हेतु अभियान चलाया गया। पन्ना जिले में भी कलेक्टर श्रीमती ऊषा परमार द्वारा इस मिशन हेतु समिति बनाई गई, जिसका नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी को बनाया गया। इस समिति के सदस्य आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय और धर्मार्थ शाखा प्रभारी मनोज पाण्डेय द्वारा जिले विभिन्न मंदिरों और निजी संग्रहों से लगभग 64 हजार से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियां ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड कर मध्य प्रदेश में छठवां स्थान और सागर संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पन्ना जिले में रीतिकालीन कवि केशवदास कृत कविप्रिया, रसिक प्रिया और महाकवि जयदेव रचित गीत गोविंद की दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां प्राप्त हुई। इस उपलब्धि के लिए संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त मदन कुमार आईएएस ने अर्ध शासकीय पत्र लिखकर आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय की प्रशंसा की। इस पत्र पर पन्ना कलेक्टर श्रीमती ऊषा परमार और जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, जिला आबकारी अधिकारी मुकेश मौर्य ने आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय को बधाई दी।

एमएसएमई के नाम पर अपात्र उद्योगों के साथ अनुदान का बड़ा खेल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। एमएसएमई याने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जिसका उद्देश्य रोजगार के क्षेत्र में इकाईयो की स्थापना करना एवं व्यापार को बढ़ावा देना है। वर्तमान समय पर जैसा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। जहां एमएमएमई की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिये।

किन्तु देखा जा रहा है कि एमएसएमई के नाम पर उस तरह का कार्य नहीं हो रहा जिस तरह कल्पना की जा रही है। किन्तु पता चलता है कि इस योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से न होने के कारण पात्रों के स्थान अपात्रों को लाभ दिया गया है। जिससे शासन को करोड़ों की क्षति पहुचाई जा चुकी है।

अपात्र एवं बंद उद्योगों को अनियमित सब्सिडी का लाभः- नियम कहता है कि एमएमएमई प्रोत्साहन योजनाओं में दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले या अपात्र उद्योगों की सूची में उद्योगों को पूंजीगत अनुदान नहीं दिया जाना चाहिये। प्रत्येक वर्ष जब दिशा निर्देश जारी होते हैं तो अपात्र उद्योगों की सूची दिशा निर्देशों में जोड़ दी जाती है। इसके साथ ही एमएसएमई योजनाओं में प्रावधान यह भी है कि इन योजनाओं के तहत पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने वाले उद्योगों को उत्पादन दिनांक से कम से कम तीन साल या पांच साल संचालन में रहना होगा। जो उद्योग अपना कारोबार तीन या पांच साल तक जारी नहीं रख पायेंगे उन्हें बंद उद्योग माना जायेगा। ऐसे उद्योगों से ब्याज सहित पूंजीगत सब्सिडी की वसूली की जायेगी। बावजूद इसके अपात्र उद्योगों को पूंजी अनुदान का लाभ दिया गया। जो इस बात का परिचायक है कि एमएमएमई में पूंजी अनुदान के नाम पर बंदरबांट का खेल किया गया है।

दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को अनुदानः- एमएसएमई में अनुदान का बंदरबांट कई तरह से किया गया। जैसे कोई आटा मिल 50 लाख की लागत से स्थापित की जाती है जहां उसे 25 लाख का अनुदान दिया जाता है।

बंद इकाईयों से वसूली नहीं हुई

नियम है कि पूंजी अनुदान से स्थापित होने वाली इकाईयों को तीन या पांच साल तक संचालित रहना चाहिये तभी अनुदान की पात्रता होगी। इसके लिये आवश्यक था कि ऐसी ईकाईयों के निगरानी होनी चाहिये। किन्तु जिला स्तर पर ऐसी इकाईयों की निगरानी नहीं हुई। जबकि स्थापित कई ईकाईयों की स्थिति खराब थी एवं बंद हो चुकी थी। बावजूद इसके उन्हें तीन साल व पांच तक संचालित मानते हुये अनुदान का लाभ दिया गया। इन योजनाओं के तहत पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने वाले उद्योगों को उत्पादन दिनांक से कम से कम तीन साल या पांच साल संचालन में रहना होगा।कोई इकोई एक साल पहले बंद हो गई तो कोई इकाई स्थापना के कुछ साल या महीने में ही बंद हो गई।

बारिश में निर्माणाधीन डायवर्सन बना दलदल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। लोक निर्माण विभाग द्वारा पवई से लगभग 7 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कराए जा रहे पुलिया निर्माण कार्य में एक बार फिर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

कुछ दिन पूर्व निर्माणाधीन पुलियों में कार्य पूरा होने से पहले ही दरारें पड़ने का मामला सामने आया था, जिसने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे। बारिश ने वैकल्पिक मार्ग (डायवर्शन) की बदहाली उजागर कर दी, जिससे क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया।

ठेका कंपनी की लापरवाही, ग्रामीण परेशान - ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया। मार्ग पर न तो पर्याप्त मात्रा में गिट्टी डाली गई और न ही मुरम एवं बजरी का उचित स्तर बिछाया गया। इसी लापरवाही के चलते थोड़ी सी बारिश में ही पूरा डायवर्शन कीचड़ में तब्दील हो गया।

कीचड़ में फंस रहे वाहन, होने लगे हादसे

ग्रामीणों के अनुसार पुलिया निर्माण के दौरान बनाया गया वैकल्पिक मार्ग बारिश के बाद पूरी तरह कीचड़ और दलदल में बदल गया। इस मार्ग से गणेशगंज, इमलिया, बड़खेरा, चंदनपुर, बिल्हा, सरसेला, खम्हरिया सहित कई गांवों के लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। हल्की बारिश के बाद ही मार्ग की स्थिति इतनी खराब हो गई कि दोपहिया वाहन फिसलने लगे और चारपहिया वाहन कीचड़ में धंस गए। कई लोगों को अपने वाहन धक्का लगाकर निकालने पड़े।

आरटीई : 8 तक कर सकेंगे विद्यालयों की च्वॉइस अपडेट

पन्ना, 04 जुलाई। राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों हेतु गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में रिक्त सीट पर तृतीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में सूचित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत आवेदक विद्यालयों की चॉइस अपडेट 3 से 8 जुलाई तक कर सकते हैं। तृतीय चरण की सीटें ऑनलाईन लाटरी के माध्यम से 10 जुलाई को प्रदर्शित की जाएंगी एवं सीट आवंटन उपरांत संबंधित विद्यालयों में प्रवेश 11 से 20 जुलाई के मध्य ले सकते हैं।

पहली ही बारिश में खुली पवई की सफाई व्यवस्था की पोल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। पवई में कचरे से पटी नालियों एवं नालों की सफाई न होने से पहली मामूली बारिश में ही गंदगी सड़कों पर आ गई, जिससे पवई नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है।

बरसात पूर्व सफाई और जल निकासी व्यवस्था को लेकर केवल औपचारिकता निभाई गई, जिसका नतीजा पहली ही बारिश में सामने आ गया। नगर का व्यस्ततम झंडा बाजार क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया, जबकि वार्ड क्रमांक-15 में बारिश का पानी सीधे घरों में घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद झंडा बाजार क्षेत्र में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सड़कों पर करीब तीन फीट तक पानी भर गया। सड़कें नाले का रूप लेती नजर आईं और पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। वाहन चालक पानी में फंसते और फिसलते रहे। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता।

ककरहटी में जल निकासी की व्यवस्था नहीं

पन्ना, 04 जुलाई। नगर परिषद ककरहटी क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था की गंभीर खामियों के कारण मुख्य मार्ग पर स्थित दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद कार्यालय के पास स्थित पुलिया और नालियां कचरे व गंदगी से पूरी तरह जाम हो चुकी हैं, जिसके कारण बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है और सड़क जलभराव के कारण तालाब जैसी स्थिति में बदल गई है। स्थानीय व्यापारी और रहवासी पिछले वर्ष 2025 से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

मंच पर विकास के दावे, मुख्य द्वार पर गड्ढे, बदहाल सड़क ने खोली पोल

नवभारत न्यूज

अमानगंज, 04 जुलाई। एक ओर जिले के तीनों विधायक, जिला अध्यक्ष और सांसद कमलापति सिंघानिया स्कूल के भव्य उद्घाटन समारोह में विकास के बड़े-बड़े दावे और उपलब्धियों का बखान करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर जेके सीमेंट प्लांट के मुख्य द्वार के सामने की सड़क बदहाल व्यवस्था की असली कहानी बयां करती दिखी।

वर्षों से गड्ढों, कीचड़ और अव्यवस्था से जूझ रहे इस मुख्य मार्ग की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है, जिसने प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के अंतर को साफ उजागर कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि क्षेत्र में फैली इस बड़ी अव्यवस्था पर प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि इसके विपरीत, सड़क किनारे छोटा-मोटा कारोबार करके पेट पालने वाले गरीब लोगों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे का आरोप लगाकर उन पर बुलडोजर कार्रवाई बहुत तेजी से की जाती है।

प्रशासन के इस दोहरे मापदंड और कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता में इस बात को लेकर गहरा असंतोष है कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर जैसा ध्यान दिया जाना चाहिए था, वैसा बिल्कुल नहीं दिया गया। लोगों का साफकहना है कि वर्षों तक सत्ता सुख भोगने के बावजूद जनप्रतिनिधि जनता की इन बुनियादी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान निकालने में पूरी तरह असफल रहे हैं। अब पन्ना की जनता के बीच यह चर्चा बेहद तेज हो गई है कि विकास केवल नेताओं के मंचों, भाषणों और विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी वास्तविक झलक धरातल पर बनी सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में साफ दिखाई देनी चाहिए।

एक अक्टूबर तक नदियों की रेत खदान प्रतिबंधित

पन्ना, 04 जुलाई। कलेक्टर ऊषा परमार ने आदेश जारी कर मानसून ऋतु की अवधि 30 जून की मध्यरात्रि के पश्चात से आगामी एक अक्टूबर तक जिले में स्थित नदियों की सभी रेत खदानों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। विदित हो कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी गाईडलाइन के तहत भारतीय मौसम विज्ञान नागपुर द्वारा मध्यप्रदेश में वर्षा ऋतु के लिए मानसून अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से नदियों से रेत खनन पर प्रतिबंध के लिए मानसून अवधि पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

शाला त्यागी बच्चों की फर्जी प्रविष्टि? निर्देशों के तहत नहीं होते प्रयास

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। जब नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो चुका है तो सरकारी स्कूलों में कई तरह के प्रयोग शुरू होते हैं। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कई जगह बहुत न्यून स्थिति में पहुंच जाती है। वहीं कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्रवेश लेने के बाद भी बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसके अलावा कई ऐसे गरीब बच्चे भी होते हैं जो स्कूलों में दाखिला तक नहीं ले पाते।

ऐसे बच्चों की खोजबीन और पहचान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये जाते हैं। किन्तु जब ऐसे आदेशों का पालन नहीं होता तो उसके परिणाम भी नहीं निकलते है। जब समीक्षा होती है तो चिन्ता व्यक्त की जाती है कि शाला त्यागी बच्चों की खोजबीन नहीं हो पाई अथवा कई जगह लक्ष्य के अनुसार बच्चों की पहचान नही की गई। जबकि निर्देश होते हैं कि खोजबीन के लिये जगह-जगह शिविरो का आयोजन किया जाय और ऐसे बच्चों की पहचान कर सूची तैयार की जाय जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ऐसे बच्चों की खोज की जाय जो स्कूल छोड़ चुके हैं अथवा स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाये। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं अन्य छात्रावासों में प्रवेश दिलाया जाय। किन्तु ऐसे छात्रावासों तक शाला त्यागी पहुंच ही नहीं पाते बल्कि फर्जी संख्या में दर्ज रहती है।

सरकारी शिक्षा में भी प्रयोग - यह भी देखा जा सकता है कि अब सरकारी शिक्षा में भी नये नये प्रयोग हो रहे हैं। इसके पीछे कारण निजी शिक्षा से प्रतिस्पर्धा करना बताया जा रहा है। यही कारण है कि कभी उत्कृष्ट विद्यालय तो कभी माडल स्कूलों का प्रयोग हुआ। वर्तमान में सीएम राईज और पीएमश्री जैसी स्कूलों का नवाचार हो रहा है। इसके चलते जो पुराने स्कूल हैं उनके प्रति जनता को मोह भंग हो रहा है। यही कारण है कि ऐसी स्कूलों में गुणवत्ता का अभाव होने के कारण प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। हर साल प्रवेश लेने वाले कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं।

पूर्व में दिए गए थे निर्देश

जिला शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि बच्चों की खोज करने के लिये कैम्प का आयोजन किया जाय। कैम्प के माध्यम से ऐस बच्चों की पहचान की जाय तो किन्हीं कारणों से स्कूल में भर्ती नहीं हो पाये अथवा प्रवेश लेने के बाद स्कूल नहीं गये। अब देखना है कि इस तरह का अभियान यहां कब तक और कहां कहां चलाया जाता है। कितने बच्चों की पहचान होती है और कितने बच्चों को प्रवेश मिल पाता है। हालांकि ऊपर से योजनायें तो बनती हैं और निर्देश भी होते हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन जिलों में नहीं हो पाता।

चंद्रावल में बारिश के बाद आवागमन मुश्किल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। जिले की ग्राम पंचायत चंद्रावल में बदहाल रास्तों ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद गांव के अधिकांश मार्ग कीचड़ और पानी से भरकर दलदल जैसे हो गए हैं, जिससे आवागमन लगभग ठप हो गया है।

स्थिति यह है कि गांव में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा है, जहां से लोग आसानी से गुजर सकें। ग्रामीणों के अनुसार, साफ-सफाई और मार्गों की नियमित देखरेख न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कीचड़ में फिसलन बढ़ने से पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है। कई लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है, जबकि दैनिक कामकाज और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न तो रास्तों की सफाई कराई गई और न ही जलभराव व कीचड़ से निजात दिलाने के लिए कोई प्रयास किया गया।

दक्षिण पन्ना के शीतल मुक्तिधाम अभियान का शाहनगर एवं सलेहा वन परिक्षेत्रों में विस्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। वन महोत्सव के अवसर पर दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा संचालित शीतल मुक्तिधाम अभियान के अंतर्गत विभिन्न मुक्तिधामों में छायादार एवं फलदार पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में सलेहा वन परिक्षेत्र के खभरी मुक्तिधाम तथा शाहनगर वन परिक्षेत्र के ग्राम महुआखेड़ा स्थित मुक्तिधाम में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

खभरी मुक्तिधाम में आयोजित कार्यक्रम में परिक्षेत्र अधिकारी जीतू सिंह बघेल, बछोन ग्राम पंचायत के सरपंच धर्मू चौधरी, ग्राम वन समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह तथा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं महुआखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच ध्रुव सिंह, ग्राम वन समिति अध्यक्ष प्रदीप सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती सदारानी, उपवन क्षेत्रपाल राम प्रसाद पटेल, सुरक्षा श्रमिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने अभियान की सराहना करते हुए इसे समाजोपयोगी एवं दूरगामी पहल बताया।

महुआखेड़ा के सरपंच ध्रुव सिंह ने कहा कि मुक्तिधामों में लगाए जा रहे छायादार वृक्ष भविष्य में अंतिम संस्कार हेतु आने वाले लोगों को विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में राहत प्रदान करेंगे तथा पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभियान के प्रथम चरण में इस वर्ष दक्षिण पन्ना वनमंडल के लगभग 10 मुक्तिधाम एवं शांति धामों का चयन किया गया है। प्रत्येक स्थल का चयन स्थानीय आवश्यकता, उपलब्ध भूमि, जनसहभागिता तथा न्यूनतम लागत जैसे व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

सोशल मीडिया पर अमीरी का दिखावा पड़ा भारी

नवभारत न्यूज

पवई 04 जुलाई। सोशल मीडिया पर महंगे मोबाइल और ठाठ.बाठ की रील्स पोस्ट करना पवई के कपड़ा व्यापारी के 19 वर्षीय बेटे अंशुल उर्फ कान्हा डेंगरे को बेहद भारी पड़ गया। रील्स देखकर युवक को अमीर समझने वाले तीन शातिर बदमाशों ने 27 जून 2026 को उसका अपहरण कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांग ली।

डरे हुए परिजनों ने बदमाशों के खाते में ?1ए48ए000 ट्रांसफर भी कर दिए थेए लेकिन पवई पुलिस की मुस्तैदी से खाता तुरंत फ्रीज करा दिया गया और युवक को सकुशल बचा लिया गया।इसके बाद आज पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों राजकमल रजकए राजकुमार पाल और शिवेंद्र सिंह को अवैध हथियारों ;एक पिस्तौलए दो कट्टेद्ध और दो बाइकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पन्ना पुलिस ने आम जनता के मन से डर भगाने और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए तीनों बदमाशों का पवई नगर के मुख्य मार्गों से पैदल जुलूस निकाला। सरेराह जुलूस निकलते ही बदमाशों की हेकड़ी निकल गई। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है।

सफाई में हर माह 15 लाख से अधिक खर्च, फिर भी शहर में कचरा ही कचरा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 04 जुलाई। स्वच्छ पन्ना सुंदर अभियान के तहत नगरपालिका द्वारा शहर की साफसफाई पर हर माह 15 लाख रूपये से अधिक की राशि खर्च की जा रही है, इसके बावजूद शहर की कॉलोनियों और मोहल्लों में गंदगी पसरी हुई है सड़क किनारे कचरे के ढेर, नालियों में जमा कूडा और बदबू से आमजन परेशान हैं।

शहर का सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका में करीब 160 सफाई कर्मचारी तैनात हैं इन कर्मचारियों के वेतन, सफाई वाहनों के डीजल, मेंटनेंस और अन्य व्यवस्थाओं पर हर माह 15 लाख से अधिक रूपये खर्च होते हैं। कई वार्डो में तो कई दिनों तक झाडू तक नहीं लगती है लोगों ने इस संबंध में कई बार सीएमओ से शिकायत भी की है। लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।

डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में भी लापरवाही- डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था भी चरमरा गई है। सफाई के लिए लगाये गये लोडिंग वाहन भी वार्डो में नहीं पहुंच रहे हैं। कई बार वाहन कवेल मुख्य सड़कों तक ही सीमित रह जाते है इससे लोगों को मजबूरी में कचरा खाली प्लॉटों या सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है।

लोग बोले स्वच्छता के नतीजे क्यो नहीं दिख रहेः- शहरवासियों का कहना है कि जब हर माह लाखों रूप ये खर्च हो रहे हैं तो फिर स्वच्छता के नतीजे जमीन पर नहीं दिख रहे। अब जरूरत है कि नगर पालिका सफाई व्यवस्था की पारदर्शी समीक्षा करे और जिम्मेदारों पर जवाबदेही तय करे, ताकि स्वच्छ पन्ना का सपना वास्तव में साकार हो सके।

सालभर पहले खरीदे डस्टबिन गायब

वर्ष 2025 में नगर पालिका ने लाखों रूपये के नए डस्टबिन खरीदे थे, जिन्हें चौक चौराहों और सड़क किनारे रखा गया था। कुछ ही महीनों में अधिकांश डस्टबिन गायब हो गये। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी भी यह नहीं बता पा रहे हैं कि ये डस्टबिन आखिर कहां गए। सड़कों के किनारे भी अब वे नहीं दिखते हैं।

अपर कलेक्टर को मिला जिला योजना अधिकारी का प्रभार

कलेक्टर ऊषा परमार ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे को जिला योजना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय पन्ना का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा है। अपर कलेक्टर आहरण एवं संवितरण अधिकारी भी होंगे।